



Neutral Citation No. -

2026:AHC:54309

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन धारा 482 बीएनएसएस संख्या - 2233 वर्ष 2026

हरपाल सिंह उर्फ हरिपाल सिंह

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता: मुकुल यादव

प्रतिवादी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या – 71

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला

1. आज न्यायालय में दाखिल किया गया दूसरा पूरक हलफनामा रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया गया है। इस दूसरे पूरक हलफनामे के माध्यम से, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने स्वयं आवेदक का हलफनामा दाखिल किया है। जबकि अग्रिम जमानत आवेदन में, जो हलफनामा दाखिल किया गया था, वह पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से दाखिल किया गया था।

2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान ए.जी.ए. उपस्थित हैं।

3. यह अग्रिम जमानत याचिका आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 3/2026, बी.एन.एस. की धारा 105 के तहत, 2023, पुलिस स्टेशन – इगलास, जिला अलीगढ़ में दायर की गई है, जिसमें मुकदमे की समाप्ति तक अग्रिम जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



4. आवेदक के विद्वानअधिवक्ता का कहना है कि आवेदक को इस मामले में झूठा फंसाया गया है। वह निम्नलिखित आधारों पर अग्रिम जमानत की मांग करता है:

i. आवेदक लगभग 63 वर्ष का एक बुजुर्ग व्यक्ति है, जो विभिन्न आयु संबंधी बीमारियों से पीड़ित है, जिनमें आंशिक पक्षाघात भी शामिल है, और उसने कोई अपराध नहीं किया है।

ii. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रारंभ में बी.एन.एस. की धारा 106(1) के तहत लापरवाही से मृत्यु का कारण बनने के लिए दर्ज की गई थी; हालांकि, बाद में इसे बी.एन.एस. की धारा 105 के तहत गैर इरादतन हत्या के अपराध में परिवर्तित कर दिया गया। अभियोजन पक्ष के इस उल्लेखनीय सुधार से अभियोजन पक्ष का मामला स्पष्ट रूप से ध्वस्त हो जाता है और आवेदक पर लगाया गया झूठा आरोप स्पष्ट है।

iii. आवेदक का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है।

5. माननीय ए.जी.ए. ने अग्रिम जमानत देने की प्रार्थना का विरोध किया है। हालांकि, उन्होंने इस तथ्य पर विवाद नहीं किया है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

6. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत दलीलों पर विचार किया है।

7. एफआईआर में आरोप है कि आवेदक ने अपने खेतों को 440 वोल्ट की बिजली की तारों से घेर रखा था। मृतक महिला अपने खेतों में सबमर्सिबल पंप बंद करने गई थी और उसे बिजली का झटका लगा, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। एफआईआर में आगे यह भी बताया गया है कि ग्रामीणों ने आवेदक को ऐसी तारों से उच्च वोल्टेज की बिजली प्रवाहित न करने की चेतावनी दी थी।

8. रिकॉर्ड में प्रस्तुत साइट प्लान से पता चलता है कि मृतक की मृत्यु आवेदक के खेत में बिजली के झटके से हुई, जहाँ कथित तौर पर एक तार बिजली के खंभे को जोड़ने वाले केबल के समानांतर चल रहा था। हालांकि, प्रत्यक्षदर्शियों माया देवी और गौरव के बयानों में आरोप लगाया गया है कि आवेदक ने जानबूझकर खेतों के चारों ओर लगे तारों में 440 वोल्ट का करंट प्रवाहित होने दिया था, लेकिन साइट प्लान में खेतों को ऐसे तारों से घिरा हुआ नहीं दिखाया गया है। इसके बजाय, इसमें केवल एक ही तार खंभे से आता हुआ दिखाया गया है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



9. उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि यह मामला गैर इरादतन हत्या के दायरे में नहीं आता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए, साथ ही आवेदक की अधिक उम्र और चिकित्सकीय स्थिति को देखते हुए, मैं आवेदक को अग्रिम जमानत पर रिहा करना उचित समझता हूँ।

10. आवेदक की अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार की जाती है।

11. आवेदक हरपाल सिंह उर्फ हरिपाल सिंह की गिरफ्तारी की स्थिति में, जो उपरोक्त मामले में अपराध से संबंधित है, उसे अग्रिम जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा, बशर्ते वह व्यक्तिगत मुचलका और दो जमानती पेश करे, प्रत्येक जमानत राशि उतनी ही हो, जो संबंधित पुलिस स्टेशन/न्यायालय के स्टेशन हाउस ऑफिसर की संतुष्टि के अनुरूप हो, निम्नलिखित शर्तों के साथ:-

i. आवेदक आवश्यकतानुसार पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए उपलब्ध रहेगा;

ii. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे वह न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से हतोत्साहित हो;

iii. आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा;

iv. आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाह पर दबाव/धमकी नहीं देगा;

12. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, संबंधित न्यायालय को जमानत रद्द करने का अधिकार होगा।

13. यह स्पष्ट किया जाता है कि ऊपर दिए गए अवलोकन केवल इस अग्रिम जमानत याचिका पर निर्णय लेने के लिए हैं और इन्हें मामले की खूबियों पर राय नहीं माना जाना चाहिए।

**17 मार्च, 2026**

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)

कुशल

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"